बारहमासी सड़कें

1520. श्रीमती सुषमा स्वराज :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में यह परिकल्पना की गई थी कि एक हजार या इससे ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के समय कितने गांव बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े थे;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त लक्ष्य को फलीभूत करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) आठवीं योजना (1992–97) में 1981 की गणना के आधार पर 1000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) सातवीं योजना के अन्त तक 26,504 ऐसे गांव थे जिन्हें बारहमासी सड़कों से जोड़ा नहीं गया था।

(ग) और (घ) गांवों को सड़कों से जोड़ने का विषय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का है। ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य योजना/बजट में निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना आयोग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों) के लिए निधियां निर्धारित करता है ताकि अन्य सड़क योजनाओं/परियोजनाओं में निधियों के अपवर्तन को रोका जा सके।

Problem of drinking water in Rajasthan

1521. SHRI RAJENDRA PRASAD MODY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have received a proposal from the Government of Rajasthan to solve the problem of drinking water in some districts of Rajasthan in collaboration with foreign countries;

(b) if so, the details thereof and the number of villages to be benefitted therefrom;

(c) the total amount to be spent on the scheme; and

(d) the time by which the scheme is likely to be approved and completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details of the projects are given as under :—

Sl. No.	Name of the Project	Name of foreign country	No. of towns and villages to be benefitted	Estimated cost (Rs. in crores)
1	Integrated Project for water Supply in the saline belts of Jhunjhunu, Churu and Sriganganagar districts	Germany	11 towns and 956 villages. As a results of the appraisal of the project by German Mission, Phase I of the Project will cover 113 villages in Sriganganagar 212 Villages of Churu district and 2 towns of Sardarsaher and Taranagar.	253.00
2	Drinking water supply for villages in Nagaur district from Indira Gandhi Nehar Project.	Sweden (Swedish International Development Authority)	Not finalised	759.00

Sl. No.	Name of the Project	Name of foreign country	No. of towns and villages to be benefitted	Estimated (Rs. in crores)
3	Project for drinking water supply in Bharatpur and Dholpur districts	—	11 towns and 1814 villages	501.10
4	Project for problematic area of Ajmer district for supply of water from Bilaspur Dam	—	205 villages situated route to Bilaspur Project	52.00 Revised to 130.00

For the project at S. No. 2, SIDA has informed that a Consultant will be appointed to review the project for preparing a feasibility report for covering two blocks only.

The Project at S. No. 3 and 4 above were returned to the State Government for revising the project/clarification on technical points.

(d) This depends upon the final respons and acceptance of the projects by the foreign countries.

प्रखंडों में ग्रामीण गरीब लोगों को रोजगार के अवसर

1522. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण गरीब लोगों को सुनिश्चित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1752 पुनर्गठत प्रखण्डों में काम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1994 तक कुल कितने पंजीकरण कराए गये हैं; और

(ग) इस योजना के अधीन 31 जनवरी, 1994 तक कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जहां वे रहते हैं वहां की ग्राम पंचायतों में अपने पंजीकृत कराने के पात्र हैं । इसलिए पंजीकरण के ब्यौरे केवल ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हैं । ये ग्राम पंचायतें इस प्रकार पंजीकृत लोगों की संख्या की सूचना खण्ड विकास अधिकारी को देंगी जो इसके पश्चात् इन ब्यौरों को समेकित करेगा और इस प्रकार पंजीकृत लोगों की संख्या की सूचना जिला कलैक्टर/उपायुक्त को देगा । यह सूचना राज्य सरकारों द्वारा उनकी वार्षिक प्रगति रिपोर्टों में दी जायेगी जो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् देय होगी ।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रगति का आकलन सृजित रोजगार के श्रमदिनों के आधार पर किया जाता है, न कि रोजगार मुहैया कराये गये लोगों की संख्या के आधार पर । राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31-1-1994 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 61.39 लाख श्रम दिनों का सृजन किया गया है ।

1523(Transferred to 9th, March 1994)

Achievements of Biotechnology

1524. SHRI DILIP SINGH JUDEV : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the standing Committee of Science and Technology and Environment and Forests has regretted that some of the achievements of Bio-technology had not reached the common man;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the main recommendations and suggestions of standing Committee for proper and successful implementation of Bio-technology in the rural areas and to reach the common man;

(d) if so, the outcome thereon; and